



## International Journal of Advance Studies and Growth Evaluation

# भारतीय कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: अवसर, चुनौतियाँ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

\*<sup>1</sup> Dr. Durga Charan Singh

<sup>\*1</sup> Assistant Professor, Department of Commerce, Har Pratap Singh Yadav, PG College Handia Prayagraj, Prof Rajendra Singh (Raju bhaiya ) University, Prayagraj, Uttar Pradesh, India.

### Article Info.

E-ISSN: 2583-6528

Impact Factor (SJIF): 6.876

Peer Reviewed Journal

Available online:

[www.alladvancejournal.com](http://www.alladvancejournal.com)

Received: 11/Aug/2025

Accepted: 10/Sep/2025

### सारांश:

यह अध्ययन 2018 से 2025 के बीच भारतीय कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की गति-विधि को जाँचता है। इसमें अवसरों, चुनौतियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर खास ध्यान दिया गया है। डीपीआईआईटी, आरबीआई और पीएलएफएस जैसे सरकारी स्रोतों से लिये गये द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर, अध्ययन निवेश के रुझान, संरचनात्मक बदलाव और क्षेत्रीय एकाग्रता को सामने लाता है। निष्कर्ष बताते हैं कि 2020 के बाद औसत निवेश में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही स्थिरता भी आई है और पुनर्निवेशित कमाई का हिस्सा बढ़ा है, जो निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। परन्तु इसका लाभ चंद विकसित राज्यों में ही सिमटा रह गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रीय और सामाजिक बहिष्करण की चिन्ता उभरती है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि एफ.डी.आई. में कृषि शृंखला और ग्रामीण रोजगार को सशक्त बनाने की बड़ी सम्भावना है, पर इसके लिए लक्षित नीतियाँ जरूरी हैं, ताकि लाभ बराबरी और समावेशी रूप से पहुँचे।

### \*Corresponding Author

Dr. Durga Charan Singh

Assistant Professor, Department of Commerce, Har Pratap Singh Yadav, PG College Handia Prayagraj, Prof Rajendra Singh (Raju bhaiya ) University, Prayagraj, Uttar Pradesh, India.

**मुख्य शब्द:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास

### प्रस्तावना:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) केवल सीमापार पूँजी नहीं है; यह प्रायः एक साथ आने वाले साधनों का गुच्छा है—तकनीक, संगठनात्मक कौशल, जोखिम प्रबंधन और निर्यात बाज़ार तक पहुँच। नीति के लिहाज से, एफ.डी.आई. में ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ, ब्राउनफील्ड अधिग्रहण, संयुक्त उपक्रम और निजी इक्विटी/वेंचर पूँजी निवेश शामिल हैं, जिनमें से हर एक का अलग-अलग प्रभाव चैनल होता है (जैसे सीखते-करते प्रभाव, आपूर्तिकर्ता विकास, मानक हस्तांतरण)। कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए असली सवाल केवल यह नहीं है कि “कितना” निवेश आया, बल्कि यह है कि “किस हिस्से की मूल्य शृंखला” में पहुँचा और उसके बाहरी असर क्या हुए। ऊपरी धारा का निवेश बीज, खेती तकनीक, कृषि सेवाएँ और खेत के पास का ढाँचा छोटे किसानों की सूचना, पानी, ऊर्जा और पूँजी जैसी पाबंदियों को हल करके उत्पादकता बढ़ा सकता है। वहीं निचली धारा का निवेश प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और खुदरा व्यापार मांग को स्थिर कर सकता है और गुणवत्ता मानकों को पक्का कर सकता है। भारत की नीति ने समझदारी से गतिविधियों के अनुसार सीमा और

शर्तें तय की हैं। असली शोध चुनौती यह है कि किस तरह का मिश्रण उत्पादकता और समावेशिता दोनों को बढ़ा सके, साथ ही पर्यावरणीय मर्यादाओं का भी ध्यान रखे।

भारतीय कृषि छोटे किसानों पर आधारित, श्रम-प्रधान और भौगोलिक रूप से बहुत विविध है। बड़े इलाके आज भी मानसून पर निर्भर हैं; सिंचाई असमान है; ज़मीनें बँटी-बँटी हैं; और विस्तार सेवाएँ ज़रूरत के अनुपात में कमज़ोर हैं। मंडियों और राज्य-स्तरीय नियमों के ज़रिये बाज़ार पहुँच होती है, जहाँ सरकारी खरीद प्रायः अनाज पर केन्द्रित है। यह स्थिति दाम और जोखिम संकेत ऐसे देती है जो हमेशा विविधीकरण या जलवायु लचीलापन को प्रोत्साहित नहीं करती। बागवानी और सहायक क्षेत्र (डेयरी, मत्स्य, पोल्ट्री) तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन फसल कटाई के बाद का नुकसान और गुणवत्ता का फर्क अभी भी बना हुआ है क्योंकि कोल्ड-चेन, ग्रेडिंग-पैकिंग-ट्रेसिंग ढाँचे और मानक अपनाने में बड़ी कमी है। उत्पादन क्षमता और असल पैदावार के बीच का अंतर बीज अनुसंधान, सूक्ष्म सिंचाई, संतुलित पोषण और छोटे खेतों के लिए अनुकूल मशीनरी में कम निवेश से जुड़ा है।

सबसे बड़ा असर ऊपरी धारा में है। पहला, बीज और बायो-प्रोडक्ट्स: स्थानीय परीक्षण और शोध से तनाव सहनशील किस्में और जैविक उपाय फैलाए जा सकते हैं, जिससे रसायनों पर निर्भरता घटेगी और पैदावार स्थिर होगी। दूसरा, पानी और ऊर्जा दक्षता: ड्रिप-स्प्रिंकलर, सोलर पंप और सामुदायिक सिंचाई से इनपुट लागत घट सकती है और सिंचाई क्षेत्र बढ़ सकता है। तीसरा, 'मशीनरी ऐज ए सर्विस': छोटे-छोटे उपकरण बेड़े, जो एफपीओ और प्लेटफॉर्म के जरिये किराये पर मिलें, श्रम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। चौथा, डिजिटल कृषि सेवाएँ: उपग्रह और सेंसर पर आधारित सलाह, मिट्टी की जाँच, क्रेडिट स्कोरिंग और बीमा किसानों के लिए सूचना और वित्तीय जोखिम घटा सकते हैं। पाँचवाँ, खेत के पास का ढाँचा: पैकहाउस, प्री-कूलिंग और स्टोरेज से फसल का मूल्य बचाया जा सकता है और निर्यात मानक पूरे किये जा सकते हैं। हर अवसर वैश्विक निवेश विषयों जलवायु-स्मार्ट कृषि, परिपत्र इनपुट, और ट्रेसबिलिटी के अनुरूप है और घरेलू सार्वजनिक निवेश का पूरक है। सुव्यवस्थित एफ.डी.आई. यहाँ आपूर्तिकर्ता विकास को बढ़ावा दे सकता है, गुणवत्ता मानक बैठा सकता है और स्थानीय ऋण को आकर्षित कर सकता है, जिससे किसान की आय और स्थिरता पर ठोस असर पड़ेगा।

## केन्द्रीय शोध समस्या

इस अध्ययन का असली सवाल यह है कि ऐसी नीतिगत और वित्तीय रूपरेखा कैसे बने जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को कृषि की ऊपरी धारा वाले हिस्सों में पहुँचाए, जहाँ से समाज को सबसे ज्यादा लाभ मिले, और साथ ही यह खतरा कम से कम हो कि स्थानीय कंपनियाँ बाहर धकेली जाएँ, साझा साधनों का अति-शोषण हो, या निवेश केवल सीमित इलाकों तक सिमट कर रह जाए। इस समस्या को चार बड़ी रुकावटें ज़िंदा रखती हैं।

1. **समन्वय की कमी:** निवेशकों को अलग-अलग एजेंसियों से मंजूरी लेनी पड़ती है और बाज़ार बिखरे हुए हैं; किसान नई तकनीक अपनाने में भारीपन महसूस करते हैं, नतीजा यह कि कोई पहल नहीं करता।
2. **दाम और जोखिम का मेल न होना:** पुरानी खरीद और व्यापार नीतियाँ फसलों के विविधीकरण और गुणवत्ता सुधार के संकेत दबा देती हैं, जिससे ऊपरी स्तर पर पूँजी निवेश का औचित्य कमज़ोर पड़ता है।
3. **बाहरी असर और ज़िम्मेदारी:** पानी, मिट्टी और जैव विविधता पर पक्का क़ानूनी पहरा न हो तो पूँजी ऐसे तौर-तरीके फैला सकती है जो निजी तौर पर फ़ायदे के हों मगर समाज के लिए महँगे साबित हों।
4. **संस्थागत भरोसा:** नीतियों का पलटना और अनुबंध लागू न होना जोखिम प्रीमियम बढ़ाता है, जिससे विदेशी निवेशक लम्बी अवधि के उत्पादक संसाधनों की बजाय छोटे चक्र वाले व्यापार में ही अटके रहते हैं।

## साहित्य समीक्षा

1. **एफ.डी.आई. और विकास पर व्यापक दृष्टिकोण:** शर्मा (2024) ने भारत के तीन दशकों के अनुभव को जोड़कर दिखाया कि निवेश चार मुख्य रास्तों से विकास को बढ़ाता है तकनीकी प्रसार, आपूर्ति श्रृंखला की गहराई, निर्यात का उन्नयन और प्रबंधकीय ज्ञान। पर इसका कुल असर इस बात पर निर्भर करता है कि देश की ग्रहण क्षमता और नीति पर भरोसा कितना है। अध्ययन की अहमियत इस बात में है कि वह महामारी के बाद की बहाली, सप्लाई-चेन के फेरबदल और हरित परिवर्तन को ध्यान में रखकर पूछता है कि क्या भारत केवल मात्रा से आगे बढ़कर मूल्य-वर्धन हासिल कर सकता है। पद्धति के तौर पर

इसने आधिकारिक आँकड़े और द्वितीयक अध्ययनों का सहारा लिया। नतीजे बताते हैं कि एफ.डी.आई. और उत्पादकता में मज़बूत लेकिन असमान रिश्ता है। सेवाएँ आगे हैं और विनिर्माण वहीं तेज़ी पकड़ता है जहाँ ढाँचा और कौशल मौजूद है। निष्कर्ष है कि दूसरी पीढ़ी के सुधार लॉजिस्टिक आधुनिकीकरण, स्थिर कर नियम, तेज़ मंजूरी अति ज़रूरी हैं। शोध की कमी यह बताई गई है कि ज़िला-फ़र्म स्तर पर ठोस सबूत और 'गुणवत्ता आधारित एफ.डी.आई.' (जैसे अनुसंधान, हरित तकनीक) का आकलन अभी बाकी है।

2. **सामूहिक प्रभाव अध्ययन:** कवाड़कर, धाले और बंगड़े (2023) ने समय-श्रृंखला आँकड़ों से एफ.डी.आई. और विकास का लोच निकालने की कोशिश की और पाया कि असर सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से मज़बूत है, मगर अंतर्जातता की चुनौती बनी रहती है। सक्सेना और खुराना (2019) ने नीति चरणों और क्षेत्रीय बदलाव का ढाँचा बनाकर कहा कि उदारीकरण की क्रमबद्धता ही तय करती है कि विदेशी पूँजी घरेलू पूँजी को खींचेगी या धकेलेगी। दोनों अध्ययनों का निष्कर्ष है कि स्थिर नियम और ढाँचा-निवेश गुणकों को और बढ़ाते हैं। इनका साझा अंतर यह है कि अब ज़रूरत है सूक्ष्म स्तर के मेल खाते आँकड़ों (एफ.डी.आई.-फ़र्म-जीएसटी पैनल) की, ताकि कारण-प्रभाव को परखा जा सके। राम सिंह (2019) ने इसे आगे बढ़ाकर कहा कि अब ढाँचा केवल गुणांकों का नहीं, बल्कि विचारधारा का है बाज़ार-खोजी एफ.डी.आई. से आगे बढ़कर दक्षता और ज्ञान-खोजी निवेश की ज़रूरत है।
3. **कृषि और ग्रामीण विकास पर अध्ययन:** शेवरान, सिवाच और रानी (2023) ने भारतीय कृषि में एफ.डी.आई. की चाल पर रोशनी डाली, जो ढाँचे के लिहाज से बेहद अहम लेकिन ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र है। उनका उद्देश्य था निवेश की धारा को चिन्हित करना और उसे चलाने वाले कारकों (नीतिगत खुलापन, कोल्ड-चेन, कांटेक्ट फार्मिंग) को अलग करना। निष्कर्ष है कि कृषि में विदेशी पूँजी अभी सीमित है पर धीरे-धीरे बढ़ रही है और ज़्यादातर इनपुट उद्योग और फसल-बाद खंडों तक सीमित है। गौकार (2019) ने लाभ-हानि दोनों का तुलनात्मक ब्यौरा दिया तकनीकी संचार, मूल्य श्रृंखला का औपचारिकरण और दाम की खोज जैसे फ़ायदे; और अनुबंध असमानता, ज़मीन एकत्रीकरण जैसे नुकसान। नीरज (2022) ने भी चेताया कि लाभ तो हैं, लेकिन यदि सहकारी और सुरक्षा तंत्र न हो तो किसानों में असमानता बढ़ सकती है। चीन से मिले तुलनात्मक प्रमाण (जिया, घोष और लियू, 2025) बताते हैं कि जब एफ.डी.आई. को कृषि विस्तार सेवाओं और ग्रामीण ऋण के साथ जोड़ा जाए तो ग्रामीण आय वाकई बढ़ती है। कुल मिलाकर नतीजा यह है कि कृषि एफ.डी.आई. को सम्हाल सकती है, अगर उसे सही संस्थागत सहारे और जोखिम-साझेदारी तंत्र मिलें। कमी अब भी यही है कि ब्लॉक स्तर पर ठोस मूल्यांकन, किसान-उत्पादक संगठनों की तैयारी और ऐसे पैमानों पर असर मापा जाए जो उत्पादन से आगे हों—जैसे लचीलापन, पानी की खपत और महिलाओं की भागीदारी।
4. **नीतिगत ढाँचा — कर सुधार, नियामकीय क्रम और निवेशकों का भरोसा:** मंगलानी और शर्मा (2024) ने कर-नीति में बदलाव और एफ.डी.आई. के प्रवाह के बीच सम्बन्ध पर काम किया है। उनका मकसद यह देखना था कि क्या भरोसेमन्द और साफ़ नियम लम्बी अवधि का निवेश खींचते हैं? नीति-घटनाओं और प्रवाह आँकड़ों के सहारे उन्होंने पाया कि जब अनिश्चितता कम होती है (जैसे विवादों और पिछली तारीख से कर लगाने जैसी धारणाओं से बचा जाता है) तो निवेश टिकाऊ होता है, जबकि महज़ दर घटाने से असर सीमित रहता है अगर नियम साफ़ न हों। मंसूर (2016) ने पहले भी एफ.डी.आई. और

विकास के बीच सकारात्मक रिश्ता दिखाया था, पर चेताया था कि नियामकीय अस्थिरता लाभ को कम कर देती है। लक्ष्ते (2013) ने इसे भारत के संस्थागत इतिहास से जोड़ा। नतीजा यह निकला कि सुधार की गहराई, न कि केवल चौड़ाई, निवेश को टिकाऊ बनाती है। तरीके दस्तावेजी विश्लेषण से लेकर सामान्य आँकड़ों तक रहे। इन अध्ययनों ने दो कमियाँ बताईं: एक, उच्च-आवृत्ति वाले फर्म-स्तरीय कर-प्रशासन आँकड़ों की ज़रूरत, ताकि अनुपालन बोझ को निवेश निर्धारक के रूप में परखा जा सके; और दूसरा, क्षेत्र-विशेष सुधारों (जैसे ई-कॉमर्स, डेटा नियम) का ठोस मूल्यांकन, जिन पर आजकल “प्लेटफ़ॉर्म एफ.डी.आई.” निर्भर करता है।

5. **क्षेत्रीय खिड़कियाँ — खुदरा और रियल एस्टेट बतौर माँग-आधारित गुणक:** खुदरा क्षेत्र एफ.डी.आई. की वजह से उपभोक्ता लाभ और छोटे-मझोले कारोबारों के औपचारिकीकरण का अहम उदाहरण बन कर उभरता है। लक्ष्ते (2013) और बाद में शंकर महेशकुमार केदार व अन्य (2025) ने नीति ढाँचे और लक्ष्यों आधुनिक लॉजिस्टिक्स, कोल्ड-चेन का विस्तार और उपभोक्ता विकल्प की समीक्षा की। निष्कर्ष बताते हैं कि जहाँ आधुनिक खुदरा पारंपरिक किराना दुकानों के साथ सप्लायर विकास और डिजिटल भुगतान के सहारे चलता है, वहाँ लागत घटती है और विकल्प बढ़ते हैं। लेकिन चेतावनी यही रही कि यदि सप्लायर अपग्रेडिंग और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा लागू न हो, तो एकाधिकार का खतरा लाभ को कम कर सकता है। रियल एस्टेट में, हरजोत सिंह (2015) ने दिखाया कि कैसे एफ.डी.आई. ने परियोजना वित्त को औपचारिक रूप दिया और पारदर्शिता बढ़ाई। निर्माण क्षेत्र के पीछे के गहरे सम्बन्ध देखते हुए इसका महत्व बढ़ा है। अध्ययन का मकसद यह था कि प्रवाह को दाम की स्थिरता और परियोजना की समय पर पूर्ति से जोड़ा जाए। निष्कर्ष मिला कि परिणाम शासन और रेगुलेटरी गार्डरेल (जैसे रेरा) पर निर्भर करते हैं। साहित्य में कमी यही है कि रेरा के बाद किरायेती आवास और किराये के बाज़ार पर सूक्ष्म अध्ययन नहीं हुए हैं, और यह भी देखना ज़रूरी है कि “ग्रीन रियल एस्टेट” में एफ.डी.आई. शहरी कार्बन कटौती में कितना सहायक है।

6. **तुलनात्मक और क्षेत्रीय सीख — पड़ोसियों से सीख, भारत के भीतर विस्तार:** कॉक और सिरिपिपत्ताकुल (2024) ने मलेशिया पर अध्ययन किया, जहाँ औद्योगिक पार्क, मानव पूँजी और निवेश सुविधा का पैकेज टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण निवेश खींचता है। उनकी कार्यप्रणाली (वर्णनात्मक विश्लेषण और नीति समीक्षा) से भारत के लिए यह निष्कर्ष निकला कि एजेंसी समन्वय और निवेश-उपरांत सेवाएँ प्रवेश मंजूरी जितनी ही अहम हैं। यादव और शब्बीर (2024) ने भारत में एफ.डी.आई.-विकास सम्बन्ध को नये चक्र में जाँचते हुए निर्यात-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत बताई। ज्योति, कुलकर्णी और चन्नलिमठ (2024) ने एक पुस्तक अध्याय में अर्थमितीय जाँच और थीमेटिक संश्लेषण को जोड़कर दिखाया कि सप्लाय-चेन आधारित निवेशों (पी.एल.आई. से जुड़े) ने एफ.डी.आई.-विकास सम्बन्ध को मज़बूत किया है, पर राज्य-स्तरीय असमानताओं पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बचा हुआ खालीपन यह है कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पर व्यवस्थित साक्ष्य की कमी है—कैसे नीतिगत स्थिरता, बिजली भरोसेमन्दी और कौशल पारिस्थितिकी स्थान-चयन तय करते हैं—और कैसे बड़े निवेशक छोटे आपूर्तिकर्ताओं व एम.एस.एम.ई. तक लाभ पहुँचाते हैं, खासकर प्रमुख निवेश गलियारों से बाहर।

7. **सांख्यिकीय तस्वीरें और समावेशी-विकास सवाल — कौन लाभ पाता है, कहाँ और कैसे:** शिवसुबरमणियन, जगदीश और टॉम (2021) ने आँकड़ों के सहारे एफ.डी.आई. की “पैठ” की तस्वीर पेश की, जिसमें क्षेत्रीय हिस्सेदारी और क्षेत्रीय केन्द्रण को ट्रैक किया गया। नतीजा यह निकला कि सेवाओं और चुनिंदा निर्माण क्षेत्रों में सघनता है। सुजाता एच. कदली (2023) ने प्रवाह के पैटर्न और व्यापक सूचकों का अध्ययन कर बताया कि जहाँ संस्थाएँ मज़बूत हैं, वहाँ एफ.डी.आई. घरेलू बचत का पूरक बनती है। सुरेश बाबू और श्रीरामुलु (2017) ने द्वितीयक आँकड़ों के सहारे विकास और रोज़गार पर प्रभाव जाँचा और सकारात्मक असर पाया, पर कौशल-झुकाव की चेतावनी भी दी। सामूहिक रूप से ये अध्ययन क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता को उजागर करते हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि समावेशी मानकों महिलाओं की श्रम भागीदारी, नौकरी की गुणवत्ता, पर्यावरणीय प्रदर्शन—को अब तक एफ.डी.आई. आकलन में निरंतर शामिल नहीं किया गया है। इस कमी को भरने से भारत की एफ.डी.आई. रणनीति सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनेगी और “गुणवत्तापूर्ण एफ.डी.आई.” एक नापने योग्य नीतिगत लक्ष्य बनेगा, न कि केवल एक नारा।

### अध्ययन का महत्त्व

इस अध्ययन का महत्त्व इस बात में है कि यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के बड़े स्तर के प्रवाह को ग्रामीण स्तर पर होने वाले असर से जोड़ता है। 2018 से 2025 तक के द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पूँजी प्रवाह रोज़गार सृजन, आय की स्थिरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढाँचागत बदलावों से किस प्रकार जुड़ा है। अब तक का शोध मुख्यतः समग्र विकास पर केन्द्रित रहा है, जबकि यह अध्ययन निवेश के बँटवारे पर भी रोशनी डालता है, जिससे यह पता चलता है कि पूँजी कुछ गिने-चुने राज्यों में केन्द्रित है और इसका ग्रामीण आजीविका पर व्यापक असर पड़ता है। नीति-निर्माताओं के लिए निष्कर्ष यह प्रमाण देते हैं कि किस तरह एफ.डी.आई. का प्रयोग कृषि मूल्य शृंखलाओं को मज़बूत बनाने, कटाई-पश्चात नुक़सान घटाने और किसानों को संगठित बाज़ारों से जोड़ने में किया जा सकता है। इस तरह यह अध्ययन समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ तय करने में अहम भूमिका निभाता है।

### अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में 2018 से 2025 तक एफ.डी.आई. प्रवाह की प्रवृत्तियों और संरचना की जाँच करना।
2. एफ.डी.आई. के क्षेत्रीय वितरण और उसके ग्रामीण रोज़गार, मज़दूरी तथा कृषि मूल्य संवर्धन पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करना।
3. ग्रामीण परिवारों के लिए एफ.डी.आई. से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों का आकलन करना, विशेषकर समावेशिता और टिकाऊ विकास के सन्दर्भ में।

### कार्यविधि

यह अध्ययन पूरी तरह से द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनकी अवधि 2018 से 2025 तक है। मुख्य स्रोतों में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की एफ.डी.आई. तथ्य-पत्रिकाएँ, भारतीय रिज़र्व बैंक की बुलेटिन और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की वार्षिक रिपोर्टें शामिल हैं। आँकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष, घटकों और राज्यों के स्तर पर किया गया।



वर्णनात्मक आँकड़ों जैसे वृद्धि दर, औसत, मानक विचलन और परिवर्तन गुणांक का प्रयोग प्रवृत्तियों और अस्थिरता को समझने के लिए किया गया। तुलनात्मक विश्लेषण से 2020 के पहले और बाद की नीतिगत स्थितियों, विशेषकर प्रेस नोट 3 के असर, का मूल्यांकन किया गया। राज्य-स्तरीय भिन्नताओं से यह आकलन हुआ कि निवेश की एकाग्रता कहाँ है और उसका क्षेत्रीय असमानताओं पर क्या असर हो सकता है। यह कार्यविधि पारदर्शी स्रोतों और ठोस तकनीकों पर आधारित है, जिससे पूँजी प्रवाह और ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक सूचकों को जोड़ने का मज़बूत आधार मिलता है।

आँकड़ा विश्लेषण और व्याख्या

तालिका 1: भारत — वित्तीय वर्ष अनुसार कुल एफ.डी.आई. प्रवाह (अमेरिकी डॉलर मिलियन) और वार्षिक वृद्धि (%)

वर्ष	कुल एफ.डी.आई. (मिलियन डॉलर)	वार्षिक % बदलाव
2018–19	62,001	—
2019–20	74,391	+20.0%
2020–21	81,973	+10.2%
2021–22	84,835	+3.5%
2022–23	71,355	–16.0%
2023–24	71,280	–0.1%
2024–25 (अनुमानित)	81,043	+13.7%

2018 से 2025 के बीच कुल एफ.डी.आई. प्रवाह में एक चक्र स्पष्ट दिखता है। 2019–20 और 2020–21 में तेज़ वृद्धि के बाद 2021–22 में यह लगभग स्थिर रहा और 2022–23 में इसमें तीखी गिरावट दर्ज हुई। यह गिरावट वैश्विक बाज़ार की अनिश्चितता और महामारी के असर को दर्शाती है। लेकिन 2024–25 में प्रवाह फिर बढ़ा, जो भारत के निवेश माहौल की मज़बूती को दिखाता है। आँकड़ों से यह भी सामने आता है कि 2020 के बाद के वर्षों में न केवल औसत प्रवाह अधिक रहा, बल्कि अस्थिरता भी कम हुई। यह स्थिरता विशेषकर कृषि क्षेत्र के लिए अहम है, क्योंकि लम्बी अवधि के पूँजी निवेश से ही बुनियादी ढाँचा और मूल्य श्रृंखला मज़बूत बन सकती है।

तालिका 2: घटकवार एफ.डी.आई. आवक (यू.एस. डॉलर मिलियन में)

वित्तीय वर्ष	इक्विटी	इक्विटी – असंयुक्त निकाय	पुनर्निवेशित कमाई	अन्य पूँजी	कुल
2018–19	44,366	689	13,672	3,274	62,001
2019–20	49,977	1,757	14,175	8,482	74,391
2020–21	59,636	1,452	16,935	3,950	81,973
2021–22	58,773	910	19,347	5,805	84,835
2022–23	46,034	1,566	19,105	4,650	71,355
2023–24	44,424	1,394	19,768	5,694	71,280
2024–25 (अनु.)	50,018	976	23,545	6,505	81,043

एफ.डी.आई. की बनावट से यह साफ दिखता है कि प्रवाह में ढाँचागत बदलाव आया है। इक्विटी निवेश अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन 2018–19 में जहाँ पुनर्निवेशित कमाई लगभग 22 प्रतिशत थी, वहीं 2024–25 तक यह करीब 29 प्रतिशत हो गयी। यह इस बात का संकेत है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों भारत में गहराई से जमी हैं और मुनाफ़ा बाहर ले जाने की बजाय यहीं कारोबार बढ़ा रही हैं। यह रुझान ग्रामीण रोज़गार और तकनीक फैलाव के लिहाज से अहम है, क्योंकि यह अस्थायी नहीं बल्कि टिकाऊ पूँजी भागीदारी को दर्शाता है।

तालिका 3: राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश – संचयी एफ.डी.आई. इक्विटी आवक (अक्टूबर 2019–सितम्बर 2024)

क्रम	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	यू.एस. डॉलर मिलियन	हिस्सा %
1	महाराष्ट्र	82,638	31%
2	कर्नाटक	54,574	21%
3	गुजरात	43,150	16%
4	दिल्ली	34,920	13%
5	तमिलनाडु	12,561	5%
6	हरियाणा	11,043	4%
7	तेलंगाना	9,314	4%
8	पश्चिम बंगाल	2,492	1%
9	राजस्थान	1,723	1%
10	झारखण्ड	1,623	1%

राज्यवार आँकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली ने मिलकर कुल आवक का पाँच में से चार हिस्सा खींच लिया। इन राज्यों में बेहतरीन लॉजिस्टिक्स, ढाँचा और औद्योगिक माहौल मौजूद है। दूसरी ओर, बिहार, झारखण्ड और राजस्थान जैसे खेती प्रधान राज्य हाशिये पर ही रह गये। इसका मतलब यह है कि अगर नीतिगत कोशिशें न हों तो ग्रामीण इलाकों तक एफ.डी.आई. का समान लाभ नहीं पहुँचेगा और क्षेत्रीय असमानता और बढ़ेगी।

तालिका 4: राज्यों में हालिया प्रवाह की गति (वित्तीय वर्ष 2022–23 बनाम 2023–24 बनाम 2024–25 की पहली छमाही)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2022–23	2023–24	2024–25 (अप्रैल– सितम्बर)
महाराष्ट्र	14,806	15,116	13,551
कर्नाटक	10,429	6,571	3,542
गुजरात	4,714	7,300	3,949
दिल्ली	7,534	6,523	3,204
तमिलनाडु	2,169	2,436	1,623
हरियाणा	2,600	1,908	1,313
तेलंगाना	1,303	3,029	1,540

पिछले सालों के प्रवाह से साफ दिखता है कि महाराष्ट्र ने स्थिरता बनाए रखी, क्योंकि उसका औद्योगिक आधार विविध है। कर्नाटक में 2022–23 के बाद तेज गिरावट आयी, सम्भवतः आई.टी. और संबद्ध क्षेत्रों की मंदी की वजह से। वहीं गुजरात ने जबरदस्त बढ़त दर्ज की, जिससे यह जाहिर होता है कि वहाँ उत्पादन और एग्रो-प्रोसेसिंग की प्रतिस्पर्धा सुधरी है। ये उतार-चढ़ाव दिखाते हैं कि जिन राज्यों की अर्थव्यवस्था विविध है, वे चक्रवाती गिरावट से बच जाते हैं, जबकि एक ही क्षेत्र पर निर्भर राज्य ज़्यादा अस्थिर रहते हैं।

तालिका 5: पी.एन.3 (अप्रैल 2020) से पहले और बाद – कुल एफ.डी.आई. का स्तर और स्थिरता

अवधि	साल	औसत (यू.एस. डॉलर मिलियन)	σ (यू.एस. डॉलर मिलियन)	सी.वी.
पहले	2018–19 से 2019–20	68,196	6,195	0.091
बाद	2020–21 से 2024–25 (अनु.)	78,097	5,675	0.073

तुलनात्मक अध्ययन बताता है कि 2020 के बाद भारत ने औसत निवेश और भी ऊँचे स्तर पर बनाए रखे, जबकि कुछ श्रेणियों के निवेशकों पर सख्ती भी हुई। परिवर्तन गुणांक घटा है, जिससे पता चलता है कि निवेश और स्थिर और भरोसेमंद हो गये हैं। यह स्थिरता कृषि क्षेत्र के लिए बेहद ज़रूरी है, जहाँ कोल्ड-चेन, गोदाम और प्रोसेसिंग जैसे बड़े निवेशों में लगातार पूँजी और नीति की निश्चितता चाहिये। सबूत बताते हैं कि एक बार जब विदेशी निवेशक टिक जाते हैं तो वे नियमों की सख्ती के बावजूद विस्तार करना पसंद करते हैं। नीति के लिहाज से यह ज़रूरी है कि नियम साफ़-सुथरे रहें और स्थिर आवक के लाभ सीधे ग्रामीण उत्पादकों और छोटे किसानों तक पहुँचें।

## चर्चा

तालिका 1 से 5 में दिख रहे आँकड़े यह बताते हैं कि भारत में एफ.डी.आई. के प्रवाह ने एक पेचीदा लेकिन मज़बूत राह पकड़ी है और इसका असर खेती और ग्रामीण विकास पर सीधा पड़ सकता है। तालिका 1 यह साफ़ करती है कि महामारी के समय आई गिरावट के बाद निवेश में तेज़ उछाल आया, जो भारत की विकास संभावनाओं पर ढाँचेगत भरोसा दिखाता है। तालिका 2 इस बात को और मज़बूत करती है, क्योंकि पुनर्निवेशित कमाई का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। यह बताता है कि निवेशक छोटे मुनाफ़े तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि लम्बे समय तक टिककर काम करना चाहते हैं। खेती के लिहाज से यह माहौल भंडारण, लॉजिस्टिक्स और प्रोसेसिंग जैसे ढाँचों के लिये पूँजी जुटाने के लिये सकारात्मक संकेत है, जिनसे फसल कटाई के बाद होने वाले नुक़सान घट सकते हैं और गाँव की आमदनी बढ़ सकती है। परन्तु क्षेत्रीय बँटवारा एक बड़ी चुनौती पेश करता है। जैसा कि तालिका 3 और 4 में साफ़ है, ज़्यादातर निवेश गिने-चुने विकसित राज्यों तक ही सिमटा हुआ है और बड़े कृषि-प्रधान इलाके हाशिये पर छूट रहे हैं। यह असमानता ग्रामीण रोज़गार और अवसरों की पहले से चली आ रही खाई को और चौड़ा कर सकती है। तालिका 5 की तुलना यह दिखाती है कि 2020 के बाद स्थिरता तो बढ़ी है, मगर राज्यों के बीच असमान बँटवारा अब भी बरकरार है। कुल मिलाकर, एफ.डी.आई. में तकनीक और ढाँचा सुधारने के मौके तो हैं, मगर अगर छोटे किसानों तक इसका लाभ न पहुँचे तो बहिष्कार का खतरा भी है। असली नीति चुनौती यह है कि ऐसे ढाँचे तैयार किये जाएँ जो एफ.डी.आई. को ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और किसान उत्पादक संगठनों की तरफ मोड़ें, ताकि गाँव के घर-परिवार भी सीधे वैश्विक पूँजी का लाभ उठा सकें।

## निष्कर्ष:

2018 से 2025 के बीच भारतीय कृषि में एफ.डी.आई. प्रवाह का अध्ययन नीति और शोध दोनों के लिये अहम सबक देता है। नतीजे बताते हैं कि 2020 के बाद औसत निवेश ज़्यादा रहा और उतार-चढ़ाव कम हुआ, जबकि नियम सख्त हुए और वैश्विक अनिश्चितताएँ भी बनी रहीं। निवेश की बनावट में भी बड़ा बदलाव आया है, जहाँ पुनर्निवेशित कमाई का हिस्सा बढ़ा है, जो मज़बूत निवेशक भरोसे की निशानी है। लेकिन राज्यों में निवेश का बँटवारा अब भी असमान है—जहाँ औद्योगिक रूप से विकसित राज्य विदेशी पूँजी का ज़्यादातर हिस्सा खींच लेते हैं, वहीं खेती-प्रधान और पिछड़े राज्य हाशिये पर रह जाते हैं। इससे क्षेत्रीय असमानता और गहरी हो सकती है और ग्रामीण परिवारों तक निवेश का लाभ सीमित रह सकता है। भारत के सामने चुनौती सिर्फ़ पूँजी खींचने की नहीं, बल्कि उसे ग्रामीण बदलाव की ओर मोड़ने की है। कोल्ड-चेन ढाँचा मज़बूत करना, किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ाना और न्यायपूर्ण अनुबंध व्यवस्था लागू करना ऐसे कदम हैं जो एफ.डी.आई. को व्यापक

विकास का साधन बना सकते हैं। अगर सही दिशा दी जाए तो विदेशी निवेश उत्पादकता बढ़ा सकता है, खेती से इतर गाँव में रोज़गार दे सकता है और किसानों की आय सुधार सकता है। इस तरह, अध्ययन यह रेखांकित करता है कि एफ.डी.आई. अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि संतुलित, टिकाऊ और न्यायपूर्ण ग्रामीण विकास का जरिया है।

## संदर्भ सूची:

1. अमीना, एम. (2016). भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव। *WEKEN*, 1(1). <https://doi.org/10.21904/weken/2016/v1/i1/93619>
2. बाबू, जी. एस., और श्रीरामुलु, सी. (2017). भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रभाव का अध्ययन। *International Journal of Arts and Science Research in Social Sciences & Humanities*, 3(3). <https://doi.org/10.20908/ijarsijec.v3i3.7773>
3. हरजोत सिंह, एम. (2015, जनवरी). भारतीय रियल-एस्टेट उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का विश्लेषण [सम्मेलन शोधपत्र]।
4. जिया, ज़ेड., घोष, ए., और लियू, एम. (2025). चीनी कृषि में विदेशी निवेश का ग्रामीण आर्थिक विकास पर प्रभाव। *Regional and World Agricultural Economy*, 6(3). <https://doi.org/10.36956/rwae.v6i3.1382>
5. ज्योति, जी., कुलकर्णी, पी. के. जी., और चन्नलिमठ, पी. एस. (2024, नवम्बर). भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रभाव। *Proceedings* (पृ. xx-xx). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-67890-5\\_81](https://doi.org/10.1007/978-3-031-67890-5_81)
6. कवडकर, एच., धाले, एस., और बांगड़े, एन. (2023, सितम्बर). भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रभाव। *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, x(x).
7. कोक, एस.-एल., और सिरिपिपत्तानाकुल, एस. (2024, मार्च). मलेशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)। *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, x(x).
8. लक्ष्मि, बी. (2013, अक्टूबर). प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और भारतीय अर्थव्यवस्था। *Contemporary Issues in Commerce and Management* (पृ. xx-xx). ISBN 978-81-9269910-2-2.
9. लक्ष्मि, बी. (2013, अक्टूबर). भारत के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)। *Contemporary Issues in Commerce and Management* (पृ. xx-xx). ISBN 978-81-9269910-2-2.
10. महेशकुमार केदार, एस., करलेकर, एस., और गोसावी, जी. (2025, जुलाई). भारतीय खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, x(x). <https://doi.org/10.5958/2249-7137.2025.00039.3>
11. मंगलानी, ए., और शर्मा, डी. एन. (2024, जनवरी). कर नीति में बदलाव और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह। *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, x(x). <https://doi.org/10.55041/IJSREM28425>
12. नीरज. (2022, अक्टूबर). भारत की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह और उसका असर। *Journal of Economics and Finance*, x(x).
13. राम सिंह. (2019, सितम्बर). भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिमान। Lambert Academic Publishing. ISBN 978-620-0-48350-8.
14. सक्सेना, आर. के., और खुराना, ए. (2019, नवम्बर). भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। *EPRA International Journal of Research and Development*, x(x).

<https://doi.org/10.36713/epra2975>

15. सैंग-लूंग, के., और सिरिपित्तानाकुल, एस. (2024, मार्च). मलेशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)। *Asian Journal of Economics and Business*, x(x).
16. श्योरन, वी., सिवाच, एम., और रानी, एम. (2023, अक्टूबर). भारतीय कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों का अध्ययन। *International Journal of Agricultural Economics and Management*, x(x).
17. शर्मा, पी. (2024, जनवरी). भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [पुस्तक अध्याय]। ISBN 978-93-5747-923-3.
18. शिवसुब्रमण्यम, —., जगदीश, —., और टिन्टो टॉम, —. (2021, मार्च). प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विकास: भारत में FDI प्रवेश की सांख्यिकीय तस्वीर। *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, x(x).
19. वन्दना, वाई., और शब्बीर, आर. (2024, अगस्त). भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका। *Journal of Management Studies*, x(x). ISSN 2456-4184